भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2302

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन्द्रों की स्थापना

2302 श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौ जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन्द्रों की स्थापना से जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से किस प्रकार लाभ होगा;

(ख) इन केन्द्रों के माध्यम से जनजातीय उद्यमियों को किस प्रकार की सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि आन्ध्र प्रदेश में ये केन्द्र लम्बे समय तक कार्य-शील तथा प्रभावी रहें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों (टीएमएमसी) की परिकल्पना जनजातीय समुदायों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जनजातीय उपज/उत्पादों के एकत्रीकरण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए और निम्नलिखित तरीकों से उनकी आय बढ़ाने के लिए की गई है:

क. कटाई के बाद और उत्पादन के बाद होने वाली हानि को न्यूनतम करना।

ख. जनजातीय उपज/उत्पादों के एकत्रीकरण/मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्राप्त उपज/उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना।

ग. जनजातीय उत्पादकों को सामूहिक विपणन और अन्य सेवाओं जैसे बाजार संबंधी जानकारी और किसानों और संभावित खरीदारों के बीच संपर्क स्थापित करने के अवसर और सहायता प्रदान करना।

घ. विभिन्न स्तरों पर बाजार संपर्क स्थापित करके और गठजोड़ के साथ एकत्रीकरण के अवसर प्रदान करके जनजातीय उपज/उत्पादों की बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर 06 टीएमएमसी को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को व्यवहार्यता/पहुंच सहित हितधारकों के साथ परामर्श सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

****